GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS WORLD PCS
Committed To Excellence
ISO 9001 Certified

01 - 15 Jan., 2019

PIB

PICTURE

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को मिली मंजूरी

PIB, (01 Jan.)
संबंधित मंत्रालय – जनजातीय कार्य मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री जुएल ओराम

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- इसके पश्चात् संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2018 संसद में पेश किया जायेगा।

अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन

- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित बदलाव किये जायेंगे :-
- नोकते, तंग्सा, तुत्सा और वांचो अनुसूचित जनजाति को अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 10 में शामिल किया जायेगा।
- "अबोर" को क्रम संख्या 1 से हटाया जायेगा, क्योंकि यह क्रम संख्या 16 में "आदि" के समान ही है।
- क्रम संख्या 6 में खाम्प्टी के स्थान पर ताई खामती का उपयोग किया जायेगा।
- क्रम संख्या 8 में मिश्मी-कमन (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) तथा ताराओं (दिगारू मिश्मी) को शामिल किया जायेगा।
- क्रम संख्या 9 में "मोम्बा" के स्थान पर मोनपा, मम्बा, सारतंग और साजोलोंग को शामिल किया जायेगा।

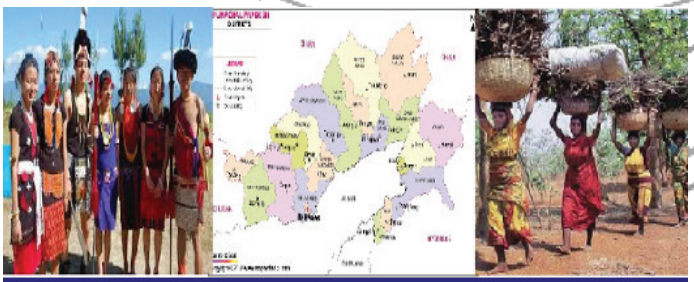

अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018

संशोधन करने की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के तहत राष्ट्रपति के पास किसी जाति, नस्ल, जनजाति, किसी जाति अथवा नस्ल के समूह को चिन्हित करने की शक्ति है।
- इस सूची में संशोधन के लिए बाद में संसद में कानून पारित करना पड़ता है।

असम समझौते की धारा-6

PIB, (02 Dec.)
संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जनवरी, 2019 को असम समझौते की धारा-6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन तथा समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों को मंजूरी दी है।
- हालाँकि, गृह मंत्रालय समिति की संरचना और शर्तों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगी।
- समिति के गठन से असम समझौते को अक्षरशः लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह असम के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा करेगा।

समिति के कार्य

- यह उच्च स्तरीय समिति असम समझौते की धारा-6 के आलोक में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान करेगी।
- समिति असम समझौते की धारा-6 को लागू करने में 1985 से अब तक किये गये कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।
- समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और असमी लोगों के लिए असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सीटों की संख्या का आकलन करेगी।

- समिति असमी और अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने, असम सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण का प्रतिशत तय करने तथा असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपायों की आवश्यकता का आकलन करेगी।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि 1979-1985 के दौरान हुए असम आंदोलन के पश्चात 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।
- समझौते की धारा-6 के अनुसार असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन की मंजूरी

PIB, (02 Dec.)
संबंधित मंत्रालय – श्रम और रोजगार मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

लाभ

- केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता।
- त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों का सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- सरकार द्वारा कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोकना।

- मुकदमेंबाजी और औद्योगिक असंतोष को कम करना।
- यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा।
- इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी।
- केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी।
- मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

PIB, (02 Dec.)
संबंधित मंत्रालय – नीति आयोग
संबंधित मंत्री – अमिताभ कांत

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 02 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है।
- इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्यों को निर्देश जारी कर सकेगी। फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के पास राज्यों को महज एडवाइजरी जारी करने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगी।

क्या है?

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की योजना है। आयुष्मान भारत के तहत सरकार देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं।
- ये जिला अस्पताल से डिजिटली लिंक होंगे। इन सेंटर्स पर जांच से लेकर इलाज और दवाई तक मुहैया कराई जाएगी।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का एक अहम हिस्सा है।
- जिसके तहत देश के 10.74 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सालाना 5 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। यानी

इन परिवारों में किसी भी सदस्य को इलाज की जरूरत पड़े, तो सरकार सालभर में 5 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी।

- देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं।
- पीएमजेएवाई से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य प्रदाताओं, आशा, एएनएम आदि के समर्पण के माध्यम से यह योजना सफल होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और इसकी संरचना

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गयी है और उसकी जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लेगा।
- निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढांचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है। गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे।
- गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक तेज गति से निर्णय लेने में सहायक होगा।
- गवर्निंग बोर्ड का गठन व्यापक है और इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में बारी-बारी से राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा।

नये कोष की स्वीकृति नहीं

- किसी नये कोष की स्वीकृति नहीं दी गई है।
- आईटी, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिए पहले स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक

PIB (03 Dec.)

संबंधित मंत्रालय – मानव संसाधन विकास मंत्रालय
संबंधित मंत्री – प्रकाश जावेडकर

संदर्भ

- राज्यसभा में 03 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक-2019 पास हो गया।
- इस विधेयक के पारित होने पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुछ संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्रदान करने का जिक्र है।
- लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम-1993 में संशोधन के लिए यह इस विधेयक को लाया गया है।

मुख्य बिंदु

- विधेयक के तहत नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति भी पूर्व प्रभाव से प्रदान की जाएगी।
- सदन में पेश किए विधेयक में एनसीटीई की स्थापना के बाद से लेकर अकादमिक वर्ष 2017-18 तक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्रदान की गई है।
- विधेयक में नए पाठ्यक्रम शुरू करने या निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण की अनुमति पूर्व प्रभाव से देने का जिक्र है।
- इस विधेयक के कानून बनने से बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त नहीं थी।
- सरकार बी. एड. शिक्षा के नये शिक्षण संस्थानों को अनुमति नहीं दे रही है। वर्ष 2020 से केवल एकीकृत बी.एड. डिग्री की पढ़ाई होगी लेकिन मान्यता दोनों पाठ्यक्रमों की होगी।
- कुछ समय तक दोनों पाठ्यक्रम रहेंगे और इसके बाद इनके बारे में फैसला होगा।

महत्त्व

- इस विधेयक का मकसद एक विसंगति को दूर करना है।
- कुछ केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों ने बिना अनुमति के बी. एड. की शिक्षा शुरू की थी और छात्रों को उपाधि दी गयी

थी। यह प्रकरण वर्ष 2011-12 से लेकर 2016-17 तक चला।

- देश भर में लगभग 17 हजार बीएड डिग्रीधारकों की डिग्री अमान्य घोषित किये जाने के संकट से बचाने के लिये कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

क्या है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद?

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 में की गई थी।
- इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हे समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं।

टाईम कैप्सूल

PIB, (04 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

संबंधित मंत्री – हर्षवर्धन

संदर्भ

- हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), जालंधर में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इजराइल के नोबल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक एवराम हेर्शको और अमेरिका के वैज्ञानिक एफ. डंकन एम. हॉल्डाने द्वारा 04 जनवरी, 2019 को वर्तमान टेक्नोलॉजी और भारत के वैज्ञानिक कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं के साथ एक टाईम कैप्सूल को जमीन में दबाया गया।
- इस टाईम कैप्सूल में 100 ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो भारत में अनुभव की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह कैप्सूल धरती में 100 वर्ष तक दबा रहेगा। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान की तकनीक के बारे में अवगत कराना है।

टाईम कैप्सूल में क्या है?

- इस टाईम कैप्सूल में 100 ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो भारत में अनुभव की जाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत के वैज्ञानिक कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू जेट की प्रतिकृतियों के अलावा, इस कैप्सूल में लैपटॉप, लैंडलाइन फोन, स्मार्ट फोन, ड्रोन, वीआर ग्लास, स्टॉपवाच, अमेजन अलैक्सा आदि शामिल हैं।
- इसमें एयरफिल्टर, इंडक्शन कूकटॉप, एयर फ्रायर आदि जैसी उपभोक्ता सामग्रियां भी शामिल हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं।
- संरक्षित किए गए कुछ अन्य उत्पादों में सोलर पैनल, नवीनतम डॉक्यूमेंट्रियों और फिल्मों सहित हार्डडिस्क, 12वीं कक्षा के छात्रों के अध्यापन में इस्तेमाल होने वाली मौजूदा विज्ञान की पुस्तकों तथा एक दर्पण रहित कैमरा शामिल हैं।

उद्देश्य

- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के छात्रों द्वारा तैयार किए गए कैप्सूल को दस फुट नीचे जमीन में दबाया गया है जो अगले 100 वर्षों के लिए जमीन के नीचे ही रहेगा।
- यहां एक पट्टिका भी लगाई गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि इस टाईम कैप्सूल को 3 जनवरी, 2119 को खोला जाएगा।
- इस टाईम कैप्सूल को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि आज यह अस्तित्व में है तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएगा और 100 साल के बाद आज की प्रौद्योगिकी की झांकी दिखाएगा।

भारत के पिछले टाईम कैप्सूल

- इंदिरा गांधी सरकार स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ को यादगार तरीके से मनाना चाहती थी। इसके लिए 15 अगस्त, 1973 को लाल किला परिसर में एक टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया गया।
- इसमें भारत की स्वतंत्रता सम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं ऐतिहासिक तथ्य शामिल थे।
- वर्ष 2010 में गुजरात सरकार ने गांधीनगर में बनने वाले महात्मा मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल दफन करवाया था।
- तीन फुट लंबे और ढाई फुट चौड़े इस स्टील सिलेंडर में कुछ लिखित सामग्री और डिजिटल कंटेट रखा गया था।

चक्रवात पाबुक

PIB, 05 Jan.

संबंधित मंत्रालय - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
संबंधित मंत्री - डॉ. हर्षवर्धन

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने चक्रवात पाबुक के लिए पीली चौकसी (yellow alert) जारी की है।
- हाल ही में थाईलैंड की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्र के ऊपर चक्रवात पाबुक उत्पन्न हुआ है।

चार चरणों की चेतावनियाँ

- राज्य सरकार के अधिकारी किसी भी चक्रवात के लिए चार चरणों में चेतावनियाँ निर्गत करते हैं।
- **पहला चरण**- इस चरण की चेतवानी को चक्रवात पूर्व सावधानी (PRE CYCLONE WATCH) कहते हैं जो चक्रवात के 72 घंटे पहले निर्गत की जाती है।
- इसमें उत्तरी हिन्द महासागर में बनने वाले चक्रवातीय क्षोभ के बारे में चेतावनी देते हुए यह बताया जाता है कि यह तेज होते हुए और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का रूप लेते हुए तटीय पट्टी के मौसम को खराब कर सकता है।

- **दूसरा चरण**- इस चरण की चेतावनी को चक्रवात चौकसी (Cyclone Alert) कहा जाता है। यह चेतावनी तटीय क्षेत्रों में मौसम के खराब होना आरम्भ होने के 48 घंटे पहले निर्गत की जाती है।
- इसमें यह सूचना दी जाती है कि यह चक्रवात कहाँ बन रहा है और इसकी तीव्रता बढ़ रही है अथवा नहीं। साथ ही, इसकी दिशा बताते हुए यह सूचित किया जाता है कि किन तटीय जिलों में यह तबाही मचाएगा।
- मछुआरों, सामान्य लोगों, मीडिया और आपदा प्रबंधकों को भी सावधान किया जाता है।
- **तीसरा चरण**- इस चरण की चेतावनी को चक्रवात चेतावनी कहते हैं। यह चेतावनी तटीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के न्यूनतम 24 घंटे पहले जारी होती है। इस चरण में बताया जाता है कि चक्रवात किस स्थान पर समुद्र पार कर भूभाग पर पहुंचेगा।
- इस चरण में हर तीन घंटे पर चक्रवात की स्थिति, तीव्रता, भूखंड पर आने के समय, साथ-साथ होने वाली भारी वर्षा, प्रबल पवनों और आंधियों के बारे में भी सूचना दी जाती है।
- **चौथा चरण**- इस चरण को भूमिपात उपरान्त का परिदृश्य कहते हैं। चक्रवात के भूभाग पर आने के 12 घंटों के पहले यह चेतावनी दी जाती है। इसमें भी चक्रवात की दिशा, भूमिपात और मौसम के बारे में सूचना दी जाती है।

चक्रवात चौकसी के विभिन्न रंग

- 2006 के मानसून के बाद से चक्रवात से सम्बंधित चेतावनी के विभिन्न चरणों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की इच्छानुसार अलग-अलग रंग दे दिए गये हैं-
- चक्रवात चौकसी - पीला।
- चक्रवात चेतावनी - नारंगी।
- भूमिपात परिदृश्य - लाल।

चाबहार बंदरगाह का परिचालन शुरू

PIB, 07 Jan.

संबंधित मंत्रालय - जहाजरानी मंत्रालय
संबंधित मंत्री - नितिन गडकरी

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने ईरान में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने 07 जनवरी, 2019 को यह बात कही।
- यह पहली बार है कि जब भारत अपने क्षेत्र के बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा।
- भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 2018 को आयोजित चाबहार त्रिपक्षीय समझौते की बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह (चाबहार) के एक हिस्से का परिचालन अपने हाथ में ले लिया है।

- चाबहार स्थित विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) के कार्यालय का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

चाबहार बंदरगाह परियोजना में शामिल

- यह कदम भारत की एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। भारत से चाबहार बंदरगाह परियोजना में शामिल होकर एक इतिहास रचा है।
- भारत चारो तरफ से थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान की मदद के लिए क्षेत्रीय सहयोग और संयुक्त प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने चाबहार बंदरगाह के बारे में ईरान के साथ वर्ष 2003 के आसपास बातचीत शुरू की थी, लेकिन इसे महत्वपूर्ण बल वर्ष 2014 की आखिरी छमाही में मिला, जिसके परिणामस्वरूप चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए मई, 2015 में दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

- इस एमओयू को चाबहार बंदरगाह को उपकरणों से लैस करने और उसका प्रचालन करने के लिए 10 साल के औपचारिक समझौते में परिवर्तित किया गया, जिसे 23 मई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान निष्पादित किया गया।
- ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रुहानी की फरवरी, 2018 की भारत यात्रा के दौरान एक अंतरिम अवधि के समझौते की आधारशिला रखी गई।
- इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच 6 मई, 2018 को औपचारिक अल्पावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

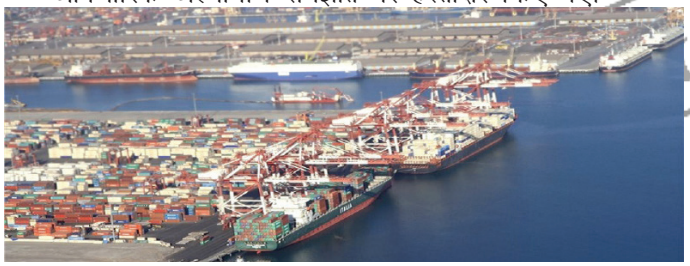

चाबहार बंदरगाह से भारत को फायदे

- चाबहार बंदरगाह का सीधा फायदा भारत के कारोबारियों को होगा। भारतीय कारोबारी अपना सामान बिना किसी रोक-टोक के सीधे ईरान तक भेज पाएंगे।
- यहां से भारतीय सामान पहुंचने के बाद इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई देशों में पहुंचाया जा सकेगा। अब तक इन देशों में जाने के लिए पाकिस्तान रास्ता रोक रहा था।
- चाबहार बंदरगाह शुरू होने से भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट खर्च काफी कम हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक एक तिहाई कम हो जाएगा। साथ ही समय भी काफी बचेंगे।

वेब वंडर वुमन अभियान

PIB, 09 Jan.

संबंधित मंत्रालय - महिला और बाल विकास मंत्रालय
संबंधित मंत्री - मेनका गांधी

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ऑनलाइन अभियान 'www.web.WonderWomen' लांच किया है।
- इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी तथा ट्वीटर की ग्लोबल हेड, पब्लिक पॉलिसी कॉलिन क्रोवेल तथा ब्रेकथ्रू की अध्यक्ष और सीईओ सोहिनी भट्टाचार्य उपस्थित थीं।
- इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने कहा कि भारतीय महिलाएं हमेशा से उद्यमी रही हैं और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुभव तथा ज्ञान के बल पर समाज पर सार्थक प्रभाव डाला है।

- उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ब्रेकथ्रू तथा ट्वीटर इंडिया के साथ साझेदारी से प्रसन्न है।

उद्देश्य

- इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं।
- इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय तथा अभियान के साझेदार का उद्देश्य विश्व की भारतीय महिला दिग्गजों की दृढ़ता को मान्यता देना है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया है।

- यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा। ऑनलाइन 'www.web.WonderWomen' अभियान का उद्देश्य ऐसे स्वरों को सम्मान और प्रोत्साहन देना है, जिन्होंने सोशल मीडिया मंचों पर सार्थक प्रभाव छोड़ा है।

मुख्य तथ्य

- इस अभियान में निर्धारित मानक के अनुसार पूरे विश्व से नामांकन के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। नामांकन 31 जनवरी, 2019 तक होगा और 6 मार्च को विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
- विश्व में कहीं भी कार्य कर रहीं या बसी हुई भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन की पात्र हैं।
- चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए खोला जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फाइनल में पहुंचने वालों का चयन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य कला, खेल, पर्यावरण संरक्षण और फैशन सहित अनेक श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।

सोलापुर एवं आगरा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन

PIB, 09 Jan.

संबंधित मंत्रालय - सड़क एवं परिवहन मंत्रालय
संबंधित मंत्री - नितिन गडकरी

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 09 जनवरी, 2019 को महाराष्ट्र स्थित सोलापुर तथा उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- प्रधानमंत्री ने सड़क परिवहन तथा संपर्क को प्रोत्साहन देते हुए 4 लेन का सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद एनएच-211 (नया एनएच-52) राष्ट्र को समर्पित किया।
- चार लेन के उस्मानाबाद राजमार्ग से सोलापुर का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से संपर्क सुधर जायेगा।

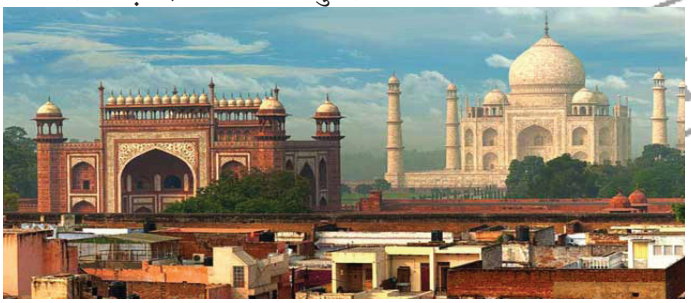

सोलापुर में आरंभ की गई परियोजनाएं

- प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकान बनाने के लिए आधारशिला रखी है।
- इन घरों से कचरा उठाने वाले, रिक्शा चालक, कपड़ा मजदूर, बीडी मजदूर जैसे गरीब बेघर लोग मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे।
- परियोजना की कुल लागत 1811.33 करोड़ रूपये है, जिसमें से कुल 750 करोड़ रूपये सहायता रूप में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे।
- प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए सोलापुर में भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा तीन जल शोधन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किये।
- इससे शहर का सीवरेज कवरेज बढेगा और शहर की स्वच्छता में सुधार होगा। नई सीवरेज प्रणाली पुरानी प्रणाली का स्थान लेगी और अमृत मिशन के अंतर्गत लागू किये जा रहे ट्रंक सीवर से भी जुड़ेगी।

आगरा में आरंभ की गई परियोजनाएं

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा स्मार्ट सिटी के लिए 1216 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाले एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र की आधारशिला रखी।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने आगरा में एस एन मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए भी आधारशिला रखी।
- गंगाजल कार्यक्रम 2,880 करोड़ रूपये की परियोजना है, यह आगरा शहर को बेहतर जल सप्लाई प्रदान करेगी। इससे आगरा के निवासियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा।
- आगरा में एस एन मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की परियोजना 200 करोड़ रूपये की है। इसमें महिला अस्पताल में 100 बिस्तर का मातृत्व इकाई बनाना शामिल है।

उन्नत मॉडल एकल खिड़की

PIB, 10 Jan.

संबंधित मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री - सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने 'उन्नत मॉडल एकल खिड़की' के विकास पर भारत और जापान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को स्वीकृति दे दी है।

लाभ

- इस एमओयू से कारोबार से जुड़े कार्यों हेतु आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए 'उन्नत मॉडल एकल खिड़की' के विकास और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों में इस पर अमल के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग सुनिश्चित होगा।
- इसके साथ ही एक ऐसे ढांचे के विकास के लिए भी भारत

और जापान के बीच सहयोग संभव होगा जिसमें ये प्रक्रियाएं त्वरित ढंग से पूरी होंगी।

- इससे देश में 'कारोबार में सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके।
- 'उन्नत मॉडल एकल खिड़की' भारत में और इससे बाहर अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों या प्रथाओं पर आधारित है।
- इसमें मापने योग्य पैमाने या मापदंड भी हैं और इससे भारत में 'एकल खिड़की' की स्थापना के मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं की पहचान हो सकेगी।
- इससे निवेश करना सुविधाजनक हो जाएगा।

वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस

PIB, 14 Jan.

संबंधित मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री - सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा, सहायक सामग्री, जूट उत्पाद, घरों के साज-सजावट के सामान और ऑफिस कार्यालय के सामानों की बिक्री करने में सहायता पहुंचाने के लिए 'वुमनिया ऑन जीईएम' पहल की शुरुआत की है।
- इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।

मुख्य बिंदु

- गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की सीईओ एस. राधा चौहान ने वुमनिया पहल के मुख्य बिन्दुओं और उसके फायदों को उजागर करने वाला तीन मिनट का एक वीडियो जारी किया है।
- उन्होंने बताया कि महिला मलिकाना वाले लगभग 80 फीसदी संगठन स्व-वित्त पोषित होते हैं और 80 लाख इकाईयों में से 60 फीसदी से ज्यादा इकाईयां सामाजिक स्तर पर पिछड़ी महिला उद्यमियों द्वारा संचालित होती हैं।
- महिलाएं अपनी कमाई की 90 फीसदी तक की राशि बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और अपने बच्चों की पढ़ाई पर निवेश कर देती हैं। ऐसे में गरीबी उन्मूलन की दिशा में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक अच्छी पहल है।
- वुमनिया होम पेज पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई पर महिला उद्यमियों की सेवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अभियान के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी।

- वुमनिया ऑन जीईएम महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा और संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5 - 'लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिला एवं लड़कियों को सशक्त करें' के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत की गई है।

चीन-भारत डिजिटल सहयोग प्लाजा (सिडकॉप)

PIB, 10 Jan.

संबंधित मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री - सुरेश प्रभु

संदर्भ

- हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एकल प्लेटफॉर्म पर भारतीय आईटी कंपनियों और चीन के उद्यमों को एक-दूसरे के और करीब लाने वाली पहल चीन-भारत डिजिटल सहयोग प्लाजा (सिडकॉप) का शुभारंभ किया गया है।

- यह गुइयांग और डालियान की नगरपालिका सरकारों के साथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) की एक साझेदारी है।
- एक भारतीय और एक चीनी कंपनी के संयुक्त उद्यम को इस प्लेटफॉर्म के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्य बिंदु

- भारत के आईटी उद्यम जटिल कारोबारी माहौल में विभिन्न आईटी टूल्स का उपयोग करके कारोबार में बदलाव लाने और परिचालन को अनुकूल बनाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
- भारतीय आईटी उद्यमों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की लम्बी एवं प्रतिष्ठित सूची है, जिनके कारोबार में बदलाव लाने और बदलते समय के साथ उनके वैश्वीकरण में उन्होंने काफी मदद की है।
- सिडकॉप, जो एक सीमा विहीन मार्केटप्लेस है, चीन के उद्यमों को यह अवसर उपलब्ध करा रहा है, ताकि उनके परिचालन को अनुकूल बनाने और कारोबार से जुड़े समाधानों (सॉल्यूशन) में सर्वोत्तम औद्योगिक तौर-तरीकों या प्रथाओं को अपनाने में उनकी मदद की जा सके।
- इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भारत के शीर्ष सॉल्यूशन प्रदाताओं के साथ जुड़ने और चीनी उद्यमों द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त सॉल्यूशन प्रदाताओं की सेवाएं लेने में किया जा सकता है।

फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड

PIB, 14 Jan.

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंसियल सम्मान से सम्मानित किया गया है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि हर वर्ष राष्ट्रीय नेता को दिए जाने वाले इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार तीन आधार बिन्दुओं पर केंद्रित है- जिसमें लोग, लाभ और प्लेनेट शामिल है।

मुख्य तथ्य

- पुरस्कार के प्रशस्तिपत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चयन ''देश को उत्कृष्ट नेतृत्व'' प्रदान करने के लिये किया गया है।
- इसके अनुसार, अथक ऊर्जा के साथ भारत के लिये उनकी नि:स्वार्थ सेवा की वजह से देश ने बेहतरीन आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास किया है।
- प्रशस्तिपत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब नवाचार और मूल्यवर्धित विनिर्माण (मेक इन इंडिया) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, लेखांकन एवं वित्त जैसे पेशेवर सेवाओं के केन्द्र के रूप में उभरी है।
- प्रशस्तिपत्र में यह भी कहा गया है कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन के लिये विशिष्ट पहचान संख्या, आधार सहित डिजिटल क्रांति (डिजिटल इंडिया) हो सकी।

कौन हैं फिलिप कोटलर?

- फिलिप कोटलर नॉर्थवेस्टरन यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग प्रोफेसर हैं।
- इन्हीं के सम्मान में हर वर्ष यह पुरस्कार देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है।
- वे मार्केटिंग (विपणन) पर 55 से अधिक विपणन पुस्तकों के लेखक है।
- बता दें कि पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करने के लिए फिलिप कोटलर की जगह इमोरी यूनिवर्सिटी के जगदीश सेठ को प्रतिनियुक्त किया गया।

डीडी साइंस और इंडिया साइंस

PIB, 15 Jan.

संबंधित मंत्रालय - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री - डॉ. हर्षवर्धन

- हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 15 जनवरी, 2019 को दूरदर्शन (डीडी) और प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्ली में विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों 'डीडी साइंस' तथा 'इंडिया साइंस' की शुरुआत की।

- केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इन दोनों महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए कहा कि यह न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार, बल्कि हमारे समाज की वैज्ञानिक सोच विकसित करने के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पहल है।
- मंत्री ने कहा कि भारत की सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन द्वारा नब्बे के दशक में पल्स पोलियो अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी।
- भारत की 92 प्रतिशत से भी अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने वाला दूरदर्शन विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम साबित होगा।

उद्देश्य

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और दूरदर्शन का उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए देश में इनकी सार्थकता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना तथा विज्ञान को और आगे ले जाना है।
- डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में देश में चौबीसों घंटे चलने वाले 'डीडी साइंस चौनल' का शुभारंभ होगा।

डीडी साइंस

- डीडी साइंस दरअसल दूरदर्शन न्यूज चैनल पर एक घंटे का स्लॉट है। इसका प्रसारण सोमवार से शनिवार तक सायं 05:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जाएगा।

इंडिया साइंस

- इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपलब्ध है और यह मांग पर निर्धारित वीडियो लाइव उपलब्ध कराएगा।
- इंडिया साइंस चैनल को किसी भी स्मार्ट फोन या इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्ट टीवी व कंप्यूटर पर देखा जा सकेगा।

मुख्य तथ्य

- विज्ञान संचार से जुड़े दो प्लेटफॉर्म विज्ञान को बढ़ावा देने और इसे रोजमर्रा की जिंदगी के करीब लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल के रूप में है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने इन चैनलों की परिकल्पना करने के साथ-साथ इन्हें मूर्तरूप देने में काफी सहयोग प्रदान किया है।

- इन दोनों चैनलों के जरिये विज्ञान आधारित वृत्तचित्र, स्टूडियो-आधारित परिचर्चाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों के आभासी पूर्वाभ्यास, साक्षात्कार और लघु फिल्मों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। ये दर्शकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होंगे।
- इनका कार्यान्वयन एवं प्रबंधन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है, जो डीएसटी का एक स्वायत्त संगठन है।

पृष्ठभूमि

- भारत में विज्ञान संचार के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले ये दोनों विज्ञान चैनल देश में एक राष्ट्रीय विज्ञान चैनल का आगाज करने की दिशा में आरंभिक कदम हैं।
- जहां एक ओर इंडिया साइंस ने पहले से ही चौबीसों घंटे वाली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है, वहीं दूसरी ओर डीडी साइंस को भी भविष्य में एक पूर्ण चैनल में तब्दील किया जा सकता है।
- वर्ष 2030 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष तीन देशों में शुमार होना होगा और इस तरह की पहल इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
- दूरदर्शन देश में तीन करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंच चुका है और विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यह एक प्रभावी माध्यम होगा।

7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन

PIB, 15 Jan.

संबंधित मंत्रालय - वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री - अरुण जेटली

संदर्भ

- हल ही में जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया है।

मंत्री समूह के दायित्व

- आवासीय निर्माण इकाइयों के लिए एक कंपोजिशन स्कीम प्रदान करके जीएसटी के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के मद्देनजर चुनौतियों सहित जीएसटी की कर की दर का विश्लेषण करना।

- रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रचना योजना या किसी अन्य योजना के लिए परीक्षण करना और सुझाव देना।
- संयुक्त विकास समझौते और उपयुक्त मॉडल में विकास अधिकारों (टीडीआर) और विकास अधिकारों के हस्तांतरण पर जीएसटी के विभिन्न पहलुओं की जांच करना।
- संरचना और सुझाव तंत्र में भूमि या किसी अन्य संघटक को शामिल करने की वैधता की जांच करना।
- जीएसटी के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों से अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है, लॉ कमेटी और फिटमेंट कमेटी के संयोजक जीओएम की सहायता करेंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में 01 जुलाई, 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है।
- इसके तहत केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गयी है, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी।
- भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।
- जीएसटी अलग-अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी,सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, लक्जरी टैक्स, सर्विस कर इत्यादि की जगह अब केवल जीएसटी ही लग रहा है।
- जीएसटी वह कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर ही लागू किया गया है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में चर्चा में रहे अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) बिल, 2018 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति के पास किसी जाति, नस्ल, जनजाति के समूह को चिन्हित करने की शक्ति प्राप्त है।
   (ii) इस बिल के द्वारा किसी राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में बदलाव किया जा सकता है।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)
2. हाल ही में चर्चा में रहे असम समझौते की धारा 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) इस समझौते को लागू करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने हेतु मंजूरी प्रदान की।
   (ii) इस समझौते हेतु गठित समिति वैधानिक के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान करेगी।
   (iii) इस समझौते हेतु गठित समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी तथा संबंधित राज्य के लोगों के लिए विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सीटों की संख्या का आकलन करेगी।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (ii)
   (b) (i) और (ii)
   (c) (ii) और (ii)
   (d) (i), (ii) और (iii)
3. हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) इससे सरकार द्वारा कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोका जा सकेगा।
   (ii) इससे मुकदमेंबाजी तथा औद्योगिक असंतोष को कम किया जा सकेगा।
   (iii) केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान किया जाएगा।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल (i)
   (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii)
   (d) इनमें से कोई नहीं

4. हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) यह योजना आयुष्मान भारत का एक अहम हिस्सा है।
   (ii) इस योजना के अन्तर्गत देश की एक जनसंख्या समूह को चिकित्सकीय सेवाओं हेतु सरकार वर्षभर में 5 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी।
   (iii) इस योजना के अन्तर्गत लगभग 13,000 अस्पतालों को शामिल किया गया।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (i)
   (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii)
   (d) (i), (ii) और (iii)

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को भंग कर इसके स्थान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया।
   (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) भारत सरकार की एक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधि नियम, 1993 में की गई।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i), न ही (ii)

6. हाल ही में चर्चा में रहे टाईम कैप्सूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) इस कैप्सूल में 100 ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है जो देश में अनुभव की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
   (ii) इस कैप्सूल को हाल ही में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इसे जमीन के अन्दर दबाया गया।
   (iii) इसका उद्देश्य आनेवाली पीढ़ियों को वर्तमान की तकनीक के विषय में अवगत कराना है।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (iii)
   (b) (i) और (iii)
   (c) (ii) और (iii)
   (d) (i), (ii) और (iii)

7. हाल ही में आए चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति हुई थी-
   (a) बंगाल की खाड़ी में
   (b) अरब सागर में
   (c) थाईलैंड की खाड़ी के आस-पास
   (d) इनमें से कोई नहीं

8. हाल ही में चाबहार बन्दरगाह का परिचालन शुरू किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) भारत अपने क्षेत्र के बाहर पहली बार किसी बन्दरगाह का परिचालन करेगा।
   (ii) इस बन्दरगाह के प्रारम्भ होने से भारतीय समानों के एक्सपोर्ट खर्च में काफी कमी आएगी।
   (iii) इस बन्दरगाह के माध्यम से भारतीय सामान चारों ओर थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान व मध्य एशिया के विभिन्न देशों में पहुँचाया जा सकेगा।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) (i) और (iii)
   (c) केवल (iii) (d) सभी सत्य है।

9. हाल ही में चर्चा में रहे वेब वंडर वुमेन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) इस अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में प्रारम्भ किया गया।
   (ii) इसका उद्देश्य वैसी महिलाओं को खोजना जो सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) हाल ही में आगरा शहर को बेहतर जल सप्लाई प्रदान करने के उद्देश्य से गंगाजल कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
   (ii) हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास हेतु भारत और जापान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   (i) हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एकल प्लेटफार्म पर भारतीय आईटी कंपनियों एवं चीनी उद्यमों को करीब लाने हेतु चीन-भारत डिजिटल सहयोग प्लाजा (सिडकॉप) की शुरुआत की गई।
   (ii) सिडकॉप एक सीमा विहीन मार्केटप्लेस है जो चीन के उद्यमों के परिचालन को अनुकूल बनाने व कारोबार से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान करने में सहायता करती है।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

12. हाल ही में चर्चा में रहे वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    (i) इससे महिला उद्यमियों के आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा जिससे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5-"लैंगिक समानता हासिल करने व सभी महिला एवं लड़कियों को सशक्त' करने के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
    (ii) इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सहायता मिलेगी।
    (iii) इस पहल को वित्त मंत्रालय की देख-रेख में चलाया जा रहा है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    (a) केवल (i)
    (b) (i) और (ii)
    (c) (i) और (iii)
    (d) (i), (ii) और (iii)

13. हाल ही में चर्चा में रहे 'फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    (i) यह पुरस्कार फिलिप कोटलर के सम्मान में हर वर्ष किसी देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है।
    (ii) यह पुरस्कार लोग, लाभ व प्लेनेट जैसे तीन आधार बिन्दुओं पर केन्द्रित है।
    (iii) इस वर्ष यह सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में प्रदान किया गया।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    (a) केवल (ii) (b) (i) और (ii)
    (c) (ii) और (iii) (d) (i), (ii) और (iii)

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    (i) इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित चैनल है जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपभोक्ताओं के मांग पर निर्धारित वीडियो लाइव उपलब्ध कराएगा।
    (ii) डीडी साइन्स व इंडिया साइन्स कार्यक्रमों का प्रबंधन व कार्यान्वयन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है, जो डीएसटी का एक स्वायत्त संगठन है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    (i) हाल ही में जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया।
    (ii) वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू एक महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है।
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
    (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

उत्तर (16-31 दिसंबर, 2018)

1. (d), 2. (a), 3. (c), 4. (d), 5. (c), 6. (d), 7. (d), 8. (c), 9. (d), 10. (c), 11. (d), 12. (d), 13. (d), 14. (c), 15. (d), 16. (c), 17. (d), 18. (c), 19. (d), 20. (c)

GS World Committed To Excellence